

श्री सभापति : क्या एम० पी० को शूगर खिला कर खामोश कर रहे हैं ?

राव बरेन्द्र सिंह : बहुत ठीक कह रही हैं कि दिल्ली में कोटा ज्यादा है। अमृतसर में अगर उन्होंने 11 रुपये या 12 रुपये खरीदी होगी तो वे किसी ब्लैक मार्केटियर की दुकान पर चली गई होंगी। इसलिए वो वहां जाना छोड़ दें . . .

(Interruptions)

SHRIMATI RAJINDER KAUR: The information is not correct. I know there is a quota of not more than 2'50 grams per head in Punjab... (Interruptions) Sir, I am unable to understand the figures quoted by the hon. Minister.

SHRI PILOO MODY: The Minister may explain the difference between black-market and open-market.

MR. CHAIRMAN: Will you go and instruct him?

SHRI PILOO MODY: This requires a certain receptivity which I do not find.

MR. CHAIRMAN.- I am thinking of the knowledge which you possess.

Hiring of godowns by FCI

*422. SHRI INDRADEEP SINHA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Food Corporation of India has taken some godowns on hire at Kandla port; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR RAM): (a)

Yes, Sir.

(b) The Food Corporation of India has a total hired covered capacity of 17,560 tonnes at Kandla Port and Gandhidham of which the capacity hired

from the Kandla Port Trust is 12,560 tonnes, from the Central Warehousing Corporation 4,000 tonnes and from private party 1,000 tonnes.

SHRI INDRADEEP SINHA:

Mr. Chairman, Sir, unfortunately the hon. Minister has not replied to the question. The query was if the Food Corporation of India had taken some godowns on hire and, if so, what are the details thereof. Among the details I would like to know whether some wheat which was meant for export arrived at Kandla Port and instead of storing it at Kandla Port, it was sent to Gandhidham for storage, brought back to Kandla Port for export and in unloading the wagons so much delay was caused that the Food Corporation of India had to pay a demurrage of several lakhs of rupees. Is it a fact? If it is not a fact, then what is the truth? Let the hon. Minister inform the House as to what action has been taken in this connection.

RAO BIRENDRA SINGH: What demurrage was paid and what delays took place in movement from one place to another and back does not form part of this question and I could not get the information. If the hon. Member had informed us about the details that he wanted, we certainly would have supplied him the information. This particular capacity of 1000 tonnes taken from a private party was done in an emergency because Kandla Port is a very congested port. There is a lot of export from that port. There are some consignments of gift articles also that India gets from outside the country. This was rented only last month on 26th of November. It is for 1000 tonnes capacity and this is on a month-to-month basis. As soon as we find that this storage is not required, as the F. C. I. has considerable storage capacity and the Central Warehousing Corporation has storage capacity, this will be given up.

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir, I would like to draw your attention to the fact that there are 3 unstarred questions precisely on this subject where this information has been asked for.

Unfortunately, according to the practice followed here, I am informed that we can get the replies to the Unstarred Questions only at 12 o'clock, that is, after the Question Hour is over. If I could get the replies earlier, I could have used them in putting the supplementary.

MR. CHAIRMAN: Then you wait till 12 o'clock.

SHRI INDRADEEP SINHA: No, Sir. That was only to draw your attention that in future the answers to the Unstarred Questions should be made available...

MR. CHAIRMAN: That is a suggestion.

SHRI INDRADEEP SINHA: ... to the Members of the House at 11 o'clock. Now, about the question. ...

MR. CHAIRMAN: Oh, that is all just by the side

SHRI INDRADEEP SINHA: About the question, Sir, the hon. Minister has not yet replied to any query whether wheat and rice meant for export from the country, when they arrived at the Kandla Port, were taken to another place and brought back to the Kandla Port, and whether that involved additional cost, and if so, what was the reason for this.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, I have already replied to that. I said that I don't have the details of what foodgrains, if any, were stored there and where the movement took place and what was the delay involved. If the hon. Member writes to me, I will let him know full details.

SHRI U. R. KRISHNAN: Sir, I would like to know from the hon. Minister how many godowns have been hired by the FCI throughout India and what the rents are that are paid annually. I would further like to

know whether it is a fact that the FCI is advancing money for the construction of godowns and if so, what the details are.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, the question relates only to the Kandla Port. Let him put a separate question-

श्री जे० के० जैन : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो गोडाउन कांडला में ले रखे हैं, उनकी लिस्ट हमें बताने की कृपा करेंगे। क्या उस लिस्ट के अन्दर कान्ति देसाई, पद्मा देसाई और उनके परिवार के गोदाम भी हैं जो उन्होंने एफ० सी० आई० को जनता सरकार के शासन में किराए पर दिये थे और उनको कितना रुपया किराए के रूप में दिया जा रहा है और गोडाउन्स बनाने के लिए क्या उनको एडवांस भी दिया गया था ?

राव बरेन्द्र सिंह : जनाब, बता दिया है कि सिर्फ एक पार्टी से एक हजार टन की कैपेसिटी की स्टोरेज किराए पर ली गई है।

श्री पीलू मोदी : इनका नाम है जैन।

राव बरेन्द्र सिंह : वह इस वक्त तो सिर्फ एक पार्टी है। सिर्फ एक हजार टन की कैपेसिटी ली गई है कांडला में।

एक माननीय सदस्य : नाम बताइये।

राव बरेन्द्र सिंह : नाम है उसका राज कुमार गोडंका सिर्फ एक पार्टी से . . .
(Interruptions)

श्री पीलू मोदी : . . . (Interruptions)
नाम है उसका राजकुमार जैन . . .
(Interruptions)

श्री सनुभाई पटेल : गोडंका कौनसा रिश्तेदार है इनका . . . (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Bhan-dari an, then Mr. Rameshwar Singh. I have got the names in that order.

SHRIMATI AMARJIT KAUR: You never look to this side, Sir.

MR. CHAIRMAN: You were late.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि पिछले दो वर्षों में प्राइवेट पार्टीज से कितनी गोदाम की जगह किराये पर ली गई और उसका कितना किराया दिया गया ? क्या यह बात सच है कि जितना किराया दिया जा रहा है, सरकार उसी जगह पर एंडीशनल गोडाउन्स फसिलिटो खड़ी करके अपने इस किराए को बचा सकती है ? एक्सपोर्ट किये जाने वाले आइटम को भी क्या आप अपने गोदाम में रखने के लिए जगह देते हैं, या सीधा पोर्ट में रखा जाता है ?

राव बोरेंद्र सिंह : फूड कारपोरेशन की सारे इंडिया की कैपसिटी 77.23 लाख टन है और 81.96 लाख टन की कैपसिटी की हायर किया जाता है, जिसमें सेंट्रल वैंयर-हाऊसिंग कारपोरेशन, स्टेट वैंयरहाऊसिंग कारपोरेशन की भी स्टोरेज शामिल है और जो खुले प्लेटफार्म पर रखते हैं, वह भी 58 लाख टन के करीब सामान रखा जाता है। तो इसमें प्राइवेट पार्टीज से किस-किस जगह कितनी और कैपसिटी ली गई, इसमें सारे हिन्दुस्तान की पार्टीज के मुतलिक मैं बता तो सकता हूँ—जितनी मेरे पास इस वक्त इन्फर्मेशन है, सात लाख अड़तालीस हजार टन टोटल सारे हिन्दुस्तान का है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उनके किराए के बारे में नहीं बताया।

राव बोरेंद्र सिंह : अब किराए का और उनके नामों का डीटेल्स मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री रामेश्वर सिंह : सभापति जी, मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि कांडला में आपका फूड कारपोरेशन का गोदाम है, और भी देश के विदेश के जो गोदाम हैं, क्या आप 250 लाख टन फूडग्रेन (गेहूँ) स्टोर करते हैं और इसमें लागत खर्च जोड़ कर 16 रु० प्रति बोरा पर लगाते हैं और इसको लेकर 161 रु० क्विंटल पड़ता है और उसको आप 130 रु० क्विंटल के हिसाब से मार्केट में

देते हैं ? और क्या यह सही है कि आपके फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के कर्मचारी लोग इन गोदामों से 60 लाख टन गेहूँ रद्दी के भाव में दिखा कर कि यह मनुष्य के खाने के लायक नहीं है उसको 131 रु० के भाव में बेच देते हैं और उन आड़तियों को बेच देते हैं जो अपने फ्लोर मिल में आटा बना कर मार्केट में बेचते हैं जिससे सरकार को 200 करोड़ रुपये का नुकसान हर साल होता है। इस धांधली को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है ?

SHRI R. R. MORARKA: You are very right.

राव बोरेंद्र सिंह : इस सवाल में तो यह नहीं आता। यह तो प्रश्न संख्या 430 से संबंधित है जो दसवें नम्बर पर है आनरेबल मेम्बर के ...

श्री रामेश्वर सिंह : नहीं मेरा नहीं है वह।

राव बोरेंद्र सिंह : किसी और आनरेबल मेम्बर का है, श्री राम लखन प्रसाद गुप्त...

श्री रामेश्वर सिंह : 422 नं० के सवाल से यह प्रश्न उठता है श्रीमन्।

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, would you kindly see that this question falls under Question No. 430 and he has jumped in advance of 8 question?

श्री रामेश्वर सिंह : उसका भी जवाब इसी में होने दीजिए।

RAO BIRENDRA SINGH: No, no. That question will come at the 10th position.

श्री रामेश्वर सिंह : इसी में दे दीजिए।

राव बोरेंद्र सिंह : कैसे दे दूँ।

श्री रामेश्वर सिंह : 422 नम्बर पर जो सवाल है और 422 नम्बर के सवाल के अंतर्गत मैंने पूछा है कि जो गोदाम आपने देश में खोल रखे हैं क्या यह सही है—श्रीमन् मेरे पास आंकड़े हैं—250 लाख टन सालाना इकट्ठा करते हैं।

श्री सभापति : आपने अपने 430 नम्बर के सवाल पर ...

श्री रामेश्वर सिंह : नहीं मैंने इसी 422 नम्बर पर पूछा है कि कांडला में और देश के विभिन्न हिस्सों में जो गोदाम आपने खोले हैं, किराए पर लिए हैं, उन में जो गेहूं रखते हैं, वह 250 लाख टन होता है और इस को आप मार्केट में 131 के भाव से देते हैं, और सन्सिडी रेट देकर जब कि 161 रु० 5 पैसा प्रति बोरा पड़ता है—30 रु० आप सन्सिडी देते हैं ...

MR. CHAIRMAN: I am afraid, this question will have to be ruled out. It can come only under Question No. 430 if it can reach and, thanks to you, it will never reach. Now, Question No. 423.

SHRIMATI AMARJIT KAUR; Sir, I have a very small question to ask.

MR. CHAIRMAN: I can give you one minute. We have very little time left.

SHRIMATI AMARJIT KAUR: Sir, is it a fact that there is still a shortage of godowns with the result that a large quantity of grains lies in the open? If so, what is the Government doing about it?

RAO BIRENDRA SINGH; We are trying to construct more godowns.

MR. CHAIRMAN; We will now take up Question No. 423.

Posts of Principals and Teachers lying vacant in Government Schools of Delhi

*423. DR. BHAI MAHAVIR: t
SHRI KALRAJ MISHRA;

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state;

(a) whether it is a fact that many posts of Principals, Post Graduate

the question was actually asked on the floor of the House by Dr. Bhai Mahavir.

Teacher, and other teachers are lying vacant in the Government Schools of Delhi;

(b) if so, what are the details of such posts in each category and since when they have remained unfilled;

(L) whether the teacher, of Delhi have been requesting the Delhi Administration for filling up these posts promptly; and

(d) if so, what steps Government propose to take to fill up these posts?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN); (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Posts of Principals and Teachers lying vacant in Government Schools of Delhi

(a) to (d) According to information furnished by the Delhi Administration the following number of posts of Post Graduate Teachers and other categories of teachers are lying vacant. The number of posts vacant, category-wise, is as under: —

PGT (Male)	71
PGT (Female)	151
TGT & Other category (Male)	216
TGT & Other category (Female)	211

The vacancies have mainly occurred as a result of post-fixation in schools in October-November, 1980. The Teachers' Association has also brought this to the notice of the Delhi Administration.

The Delhi Administration are taking necessary steps to fill up these posts by promotion as well as by direct recruitment.